'सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरु को मिलेगा'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुसांईसर बड़ा में अंत्योदय के शिविर का अवलोकन किया

बीकानेर, 8 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से रद्द हुए सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को मिलने वाला है। ये चारों जिले बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वो सभी पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आएं तो पूछना कि उनके वादों का क्या हुआ।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीकानेर के गुंसाईसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ भी थे।

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सैंटर बनाने का काम करेंगे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ के लिए जमीन देने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए जरूरी बजट भी दिया जायेगा। कांग्रेस ने जिस व्यापारी से घोषणा कराई थी, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने व्यापारी पर दबाव बनाकर सिर्फ घोषणा करवा ली, अब वो टालमटोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक राजस्थान उत्कृष्ट नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के लिए चार हजार करोड़ रूपए दिए हैं और बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर में इससे काम होगा। किसान को पानी-बिजली और बीज देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

विधायक ताराचंद सारस्वत ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के समक्ष ट्रॉमा सैंटर बनाने की मांग रखी तथा सरकारी कॉलेज की घोषणा करने की मांग की।

ताराचंद सारस्वत के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके विधायक होशियार हैं। दो मिनट का बोला था, लेकिन पूरे तीन पन्ने का भाषण बोल दिया।

उन्होंने अपनी सभी मांगें रख दी हैं। जो काम अधूरे हैं, उनके बारे में भी बोल दिया और जो करवाने हैं, उनके बारे में भी बोल दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के गुंसाईसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और सभा को संबोधित किया।

बिहार में 47 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करवाए

नयी दिल्ली, 08 जुलाई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दो सप्ताह के अंदर चुनाव अधिकारियों को लगभग आधे मतदाताओं (47 प्रतिशत) के भरे हुए गणना-फार्म प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोग द्वारा जारी एक विज्ञिप्त में दी गयी। गणना-फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। आयोग ने कहा है कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 3,70,77,077 गणना फार्म मिल चुके हैं, जो राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं की संख्या का 46.95 प्रतिशत है। आयोग ने पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश गत 24 जून को जारी किए थे। आयोग ने पुनरीक्षण के काम के लिए इन दो सप्ताह में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित कराए हैं और सूची में दर्ज 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं (7,70,44,990) के गणना-फार्म वितरित किए जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि अब तक 18.16 प्रतिशत फॉर्म उसके ऐप ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

अश्वनी पंजाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं, अब भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को देखते हुए अश्वनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।

ट्रंप ने 14 देशों के लिए नए टैरिफ घोषित किए

ट्रंप ने इन सभी 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है

वाशिंगटन, 08 जुलाई। वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ाने वाले नए कदम में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बंगलादेश और म्यांमार सहित 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब वाइट हाउस द्वारा शुरू किए गए कुछ सबसे आक्रामक आयात करों पर 90-दिवसीय रोक इस सप्ताह समाप्त होने वाली थी। ट्रंप ने जिन 14 देशों के नेताओं को औपचारिक पत्र भेजे हैं, उनमें सहयोगी और छोटे देश भी शामिल हैं। यह पत्र इस साल एक अगस्त को लागू होने वाले टैरिफ के बारे में हैं, जो ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को दर्शाता है। पत्र में ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी दोहराई और एक अगस्त से शुरू होने वाले संभावित शुल्कों के बारे में अन्य विश्व नेताओं को सूचित किया। उच्च टैरिफ शुरू में नौ जुलाई से प्रभावी होने वाले थे लेकिन अधिकारियों द्वारा नए व्यापार सौदों पर बातचीत करने की मांग के कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया था।

- **इन देशों में जापान व दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो लम्बे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।**

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म' पर जापान और दक्षिण कोरिया को लिखे पत्र में कहा,यदि किसी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें जिस भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा।

गौरतलब है कि उच्च टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होंगे और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे पहले से घोषित सेक्टर टैरिफ के साथ नहीं जुड़ेंगे।

ट्रंप के पत्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी गई थी कि उनके टैरिफ में किसी भी वृद्धि के साथ ही अमेरिकी शुल्कों में भी वृद्धि की जाएगी। ट्रंप ने घोषणा की कि इसी तरह के पत्र 12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए, जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बंगलादेश, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उन पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिहॉन्ना के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी।

कांग्रेस ने माना कर्नाटक में पार्टी में अन्तर्कलह है

बेंगलुरू, 08 जुलाई। कर्नाटक में किसी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता की सम्भावना को खारिज करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पार्टी के कई विधायकों को कुछ शिकायतें हैं और उनसे अपनी बात लिखकर देने को कहा गया है।

- **कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से शिकायत है।**
- **लेकिन सुरजेवाला ने नेतृत्व परिवर्तन से इन्कार किया व कहा कि इस पर फैसला हाईकमान ही ले सकते हैं।**

सुरजेवाला ने कहा कि वे विधायकों की समस्याओं को एक एक करके हल करेंगे। नाराज विधायकों, बीआर पाटिल और राजू कागे ने कई मसले उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने यूनीवार्ता के एक सवाल पर कहा, कई विधायकों के पास मुद्दे और शिकायतें हो सकती हैं। मैंने उनसे कहा है कि वे ये सब मुझे लिखित में दें। हम उनका बारी बारी से हल निकालेंगे।

कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि राज्य में पार्टी में हालात काबू में हैं लेकिन आम चर्चा यह है कि शिकायतों के सामने आने से पार्टी की अंदरुनी कलह दिखने लगी है। अब सुरजेवाला ने जो रुख अपनाया है, वह बंद कमरे में बातचीत और मीडिया की निगाहों से दूर रहने का प्रयास है। उन्होंने समस्या के हल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे लगता है कि पार्टी शिकायतों के निपटारे के मामले में कोई गंभीर कदम उठाने वाली नहीं हैं।

राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर उठे सवालों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, एक पत्रकार की संपादक बनने की आकांक्षा हो सकती है, लेकिन इस फैसले की डोर तो चैनल मालिक के हाथ में होती है। सुरजेवाला के बयान नेतृत्व संबंधी फैसलों पर कांग्रेस हाईकमान की मजबूत पकड़ को दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर, सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि ये दौरे पूरी तरह से प्रशासनिक हैं। उन्होंने कहा, "वे सरकारी काम से दिल्ली जा रहे हैं- ताकि वे केन्द्र के समक्ष कर्नाटक के मसले रख सकें। यह उनका कर्तव्य है और वे इसे पूरा कर रहे हैं।"

चिराग पासवान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हत्याएं और अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह मेरे लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूँ, वह सुशासन के लिए जानी जाती है।

चिराग तो अब विपक्षी नेताओं जैसी भाषा बोल रहे हैं। यह चौंकाने वाला है।

हालाँकि अभी तो चुनाव में समय है, देखना यह होगा कि चिराग नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाज़ी को कितना आगे ले जाते हैं। यह भी देखने की बात है कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये लोकसभा सांसद और केन्द्रीय मंत्री पद से वाकई इस्तीफा दे देंगे या फिर वे सीट बंटवारे में अच्छी डील हासिल कर के पीछे हट जाएंगे?

जो भी हो, एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आने वाले हफ्तों में तकरार तेज़ होने की पूरी संभावना है।

उदयपुर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध की माँग पर सुनवाई आज होगी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 जुलाई। ज़मीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका "उदयपुर फाइल्स" फिल्म और उसके ट्रेलर के खिलाफ है। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में एक दर्ज़ी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर आधारित है। याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म एक ऐसी पक्षपाती और भड़काऊ कहानी दिखाती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और देश में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है।

याचिका के अनुसार, फिल्म का ट्रेलर यह दिखाता है कि साहू की हत्या मुस्लिम समुदाय के नेताओं की मिलीभगत से हुई थी। इस तरह की कहानी हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गंभीर दूरी और तनाव पैदा कर सकती है। याचिका की 9 जुलाई, बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है, "फिल्म का ट्रेलर मुस्लिम समुदाय को एक नकारात्मक तरीके से पेश करता है, जिससे उस समुदाय के लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिल्म बहुत भड़काऊ है और दो समुदायों के बीच फूट डाल सकती है, जिससे देशभर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।"

याचिका कहती है कि "ट्रेलर की सामग्री खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाती दिखती है, जिसमें उनके बारे में गलत और तोड़ी-मरोड़ी गई बातें दिखाकर भाईचारे को तोड़ने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद का भी ज़िक्र किया गया है, जो अभी वाराणसी की जिला अदालत और भारत के सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।"

- **यह फिल्म उदयपुर में दिन दहाड़े हुई कन्हैयालाल दर्ज़ी की नृशंस हत्या पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि मुस्लिम कट्टरपंथी युवकों ने तलवारों से काट कर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी।**
- **जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फिल्म से हिंदू-मुस्लिम वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश भर में शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।**
- **फिल्म 11 जुलाई को रिलीज़ हो रही है।**

इसके अलावा, फिल्म में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता नूपूर शर्मा के उस विवादास्पद बयान को भी दिखाया गया है, जिससे पहले देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी है।

याचिका के अनुसार, "ऐसे पुराने विवादास्पद मुद्दों को याचिका में कहा गया है कि जो पहले ही देश में दंगे फैला चुके हैं, को दोबारा दिखाकर यह फिल्म भाईचारे की भावना को कमज़ोर करती है और देश के धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए इसमें न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।"

इसके अलावा, फिल्म में ऐसे आपत्तिजनक दृश्य भी दिखाए गए हैं, जिनमें मुस्लिम मौलवियों को नाबालिग बच्चों के साथ समलैंगिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया है।

इसी कारण, याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि फिल्म और उसके ट्रेलर के रिलीज़, प्रसारण, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिए जाएं कि वह इस फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सभी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटवाए। फिल्म के निर्देशक और निर्माता के अलावा, याचिका में डिस्ट्रीब्यूटर रिलायंस एंटरटेनमैंट प्राइवेट लिमिटेड, गूगल, एक्स और मेटा को भी पार्टी बनाया गया है।

रेल मंत्री अश्विनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैष्णव समाज में परम्परा रही है कि घर के किसी वयोवृद्ध सदस्य का निधन होता है, तो बैकुंठी निकाली जाती है। अंतिम संस्कार भी पार्थिव देह को बैठाकर ही किया जाता है।

रेल मंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को पहली बार अश्विनी वैष्णव जोधपुर आए थे। इस दौरान पिता-पुत्र की मुलाकात काफी कम समय के लिए हो पाई थी, तब दाऊलाल वैष्णव ने अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी।

उन्होंने लिखा- कर्तव्य को इतनी निष्ठा से निष्पादित करो कि हर रेलयात्री का चेहरा यात्रा के दौरान फूल सा खिला रहे।

स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं सहित, शहर के लोग उपस्थित थे। अंतिम संस्कार में कागा श्मशान घाट पर सीएम भजनलाल शर्मा तथा भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ भी पहुंचे।

इज़रायल के प्र.मंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तनाव कम कराने तथा सर्बिया और कोसोवो के बीच समझौता कराने में उनके प्रयासों को अनदेखा किया। हालांकि भारत ने अधिकारिक रुप से पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में ट्रंप की भूमिका का खंडन किया है और कहा है कि आपसी बातचीत से समाधान हुआ।

ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मिस्त्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने में मदद की है, और अब्राहम समझौते (अब्राहम अकॉर्ड) के जरिए इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने में भी उनकी भूमिका रही है।

ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में खुद को एक शांति निर्माता बताया था और वादा किया था कि वे अपने बातचीत के कौशल से यूक्रेन और गाज़ा के युद्धों को जल्दी खत्म करवा देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के पांच महीने बाद भी ये दोनों संघर्ष जारी हैं।

नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में गाज़ा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर काम करने पर चर्चा हुई। उसी दौरान, इज़राइल के अधिकारी कतर में हमास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे थे, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ट्रंप ने बैठक से पहले ही अनुमान जताया था कि इस सप्ताह एक समझौता हो सकता है।

'पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक एमेज़ॉन से खरीदे गए थे'

आतंकी वित्तपोषण की वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया

नई दिल्ली, 08 जुलाई। वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया है कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक अमेजन से खरीदे गये थे। एफएटीएफ ने दावा किया कि 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को पेमेंट पेपल से हुआ था।

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एफएटीएफ ने कहा कि वित्तीय सहायता के बिना ऐसे हमले संभव नहीं थे। एफएटीएफ ने कहा था कि वह 200 अधिकार क्षेत्रों वाले अपने वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए मामलों को संकलित करते हुए, आतंकवादी वित्तपोषण का व्यापक विश्लेषण करेगा। भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग की केस स्टडी देते हुए, एफएटीएफ ने कहा कि हमले में इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक - एल्यूमीनियम पाउडर - ईपीओम अमेजन से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था।

- **एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व ऑनलाइन मार्केट प्लेस का दुरुपयोग कर रहे हैं।**

बता दें कि फरवरी 2019 में, जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर एक आत्मघाती बम विस्फोट किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 40 सैनिक मारे गए। आतंकी हमले की साजिश जैश-ए-मोहम्मद द्वारा रची गई थी।

एफएटीएफ रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहा कि आतंकवादियों ने अपने परिचालन खरीद (उपकरण, हथियार, रसायन, 3डी-प्रिंटिंग सामग्री) के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। एफएटीएफ ने कहा कि ईपीओएम का उपयोग व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं से प्रेरित होकर फंड-मूविंग उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान सेवा और वीपीएन के उपयोग पर एक केस स्टडी का हवाला देते हुए एफएटीएफ ने 3 अप्रैल, 2022 को गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के लिये पेपल के माध्यम से 669,841 रुपये (7,685 अमेरिकी डॉलर) भेजे गए थे।

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल थे। महाधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा कि उनकी ओर से याचिकाकर्ता के आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। उनके अनुरोध पर अदालत ने पूर्व में दिये आदेश को संशोधित कर दिया।

बहस के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका में कैबिनेट सब कमेटी के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा समान तथ्यों पर याचिका पेश की गई थी और उसे वापस लेने के आधार पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया था, लेकिन नई याचिका में इस तथ्य को छुपाया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश पूर्ववर्ती रिपोर्ट को किस तरह प्राप्त किया गया? यदि याचिकाकर्ता ने अनाधिकृत तरीके से यह रिपोर्ट हासिल की है तो भी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। महाधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन फेल होने पर लंबे समय बाद हाईकोर्ट आ गए। दूसरी ओर अदालत ने कहा कि सरकार याचिका को कभी प्री-मैच्योर बता रही है तो कभी उसे सारहीन बताकर खारिज करने की गुहार की रही है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार तक टालते हुए, राज्य सरकार को प्रकरण से जुड़ा रिकॉर्ड साथ लाने को कहा है।

क्या 160 वर्षों से चला आ रहा दो पार्टी सिस्टम अब टूटेगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इनकार कर दिया, जिसके कारण "कैपिटल" बिल्डिंग पर हिंसक हमला हुआ। यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि संवैधानिक संकट था।

लेकिन यह संकट केवल व्यक्तियों या पार्टियों का नहीं है। यह पूरी संरचना का संकट है। 18वीं सदी में एक छोटे, अपेक्षाकृत एकसमान गणराज्य के लिए बनाई गई राष्ट्रपति प्रणाली अब 21वीं सदी के एक वैचारिक, नस्लीय, वर्गीय और सूचना के बुलबुलों में बँटी महाशक्ति को संभालने के लिये जूझ रही है। इलेक्टोरल कॉलेज की विकृतियाँ, गेरिमांडरिंग (निर्वाचन क्षेत्रों की मनमानी रचना), और "विजेता ही सब कुछ ले जाए" व्यवस्था जनता में अलगाव और चरमपंथ को और बढ़ाती है।

अब अमेरिका की आगामी स्थिति क्या होगी। अब अमेरिका के सामने तीन संभावित रास्ते हैं: पहला है, सुधार के माध्यम से नवीकरण (रिन्यूअल थ्रू रिफॉर्म) आज की युवा पीढ़ी और दोनों दलों के उदार सोच वाले लोगों में सुधार की मांग तेज़ हो रही है। जहाँ संविधान संशोधन मुश्किल प्रतीत होते हैं, वहीं विधायी और प्रक्रियागत बदलावों से सत्ता का संतुलन दोबारा स्थापित किया जा सकता है और भरोसा लौटाया जा सकता है।

दूसरा है, गहराता ध्रुवीकरण (डीपनिंग पोलराइज़ेशन)। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह निकट भविष्य का सबसे संभावित रास्ता लगता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट समर्थक अब लगभग दो अलग-अलग देशों में रह रहे हैं-जिनके मूल्य, कानून और भविष्य की कल्पना एक-दूसरे से टकराती हैं। अगर कोई भी पक्ष चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पाता, तो लोकतंत्र की वैधता ही समाप्त हो जाएगी।

तीसरा है, अधिनायकवाद की ओर झुकाव (अथॉरिटेरियनड्रिफ्ट)। अगर संस्थागत मानदंड और कमजोर होते गए, तो अमेरिका एक "सॉफ्ट ऑथोरिटेरियन" यानी नरम तानाशाही की ओर फिसल सकता है, जहाँ एक पार्टी का वर्चस्व हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हो, और असहमति को अपराध मान लिया जाए। ज़रूरी स्थितियाँ पहले से मौजूद हैं तथा अब बस इरादे की ज़रूरत है।

लेकिन, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका का इतिहास लचीलेपन और पुनर्निर्माण का रहा है। सिविल वॉर से लेकर वॉटरगेट तक, अमेरिका ने ऐसे संकटों का सामना किया है, जो अजेय लगते थे। सवाल यह है कि क्या यह देश एक बार फिर अपने आत्मबल से खुद को सुधार सकेगा, इससे पहले कि दरारें टूटन में बदल जाएँ।

कुल मिलाकर, अमेरिकी तंत्र के भविष्य को न तो सिर्फ अदालतें तय कर सकती हैं, और न सिर्फ बैलट बॉक्स में। अमेरिकन व्यवस्था का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या इसके नागरिक और नेता दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उन गहरे मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, जो इस गणराज्य को एक सूत्र में बाँधते हैं। और वे मूल्य हैं- निष्पक्षता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति साझा प्रतिबद्धता।

अगर ऐसा नहीं हो सका, तो खतरा विदेशी नहीं होगा, वह भीतर से ही आएगा।

इलैक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष शोध तक के उद्योगों को झकझोर देने वाले अरबपति उद्यमी एलन मस्क अब एक नई दिशा में, अमेरिकन राजनीति में कदम रख चुके हैं। अपनी नई राजनीतिक पार्टी, "अमेरिका पार्टी" की शुरुआत के साथ, मस्क ने लोकतांत्रिक इतिहास की मजबूत प्रहरी, अमेरिकी द्वि-दलीय व्यवस्था की जड़ों को चुनौती देने की कोशिश शुरु कर दी है। उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है, जब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों से जनता का मोहभंग ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुका है। लेकिन क्या "अमेरिका पार्टी" सच में उस दो-ध्रुवीय प्रभुत्व को हिला सकती है, जो पिछले 160 से अधिक वर्षों से अमेरिकी राजनीति को आकार देता आया है?

दोनों बड़ी पार्टियों से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। हाल की एक गैलप सर्वे के मुताबिक, लगभग 63 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मतदाता मौजूदा व्यवस्था को अव्यवस्थित, अत्यधिक ध्रुवीकृत और आम नागरिकों की वास्तविक चिंताओं से कटी हुई मानते हैं। दक्षिणपंथ एवं वामपंथ दोनों की बढ़ती जा रहीं लोकलुभावन (पॉपुलिस्ट) भावनाओं ने राजनीतिक नेतृत्व और जनता के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। यह स्थिति किसी भी नई राजनैतिक ताकत के लाभ के लिए एक दुर्लभ सुअवसर प्रस्तुत कर रही है।

एलन मस्क एक ऐसे उभरते गठजोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। जो पारंपरिक राजनीतिक पहचान से परे है। उनकी नज़र तकनीकी उद्यमियों, जो दोनों पार्टियों से निराश हैं, और युवा मतदाताओं पर है। "अमेरिका पार्टी" उन मतदाताओं का ठिकाना बन सकती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक सोच रखते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील सोच और दक्षिणपंथी अतिवाद, दोनों से सतर्क हैं।

अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि चाहे "अमेरिका पार्टी" द्वि-दलीय प्रणाली को गिरा पाए या केवल उसमें सुधार के लिए एक धक्का दे, लेकिन एलन मस्क ने एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी है। एक ऐसा देश जहाँ राजनीतिक कल्पना अक्सर जड़ जमाकर बैठ जाती है, वहाँ यह खुद में एक ऐसा झटका है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908